आबंटियों द्वारा किस्त न जमा कराने पर, तिमाही किस्त धन पर 3 प्रतिशत की शास्ति ब्याज देनी होती है। यह शास्ति ब्याज केवल विलम्ब अवधि के लिए ही लागू होगी। प्राधिकरण ने 39 प्रतिशत की ब्याज दर वसूले जाने का खण्डन किया है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) के आलोक प्रश्न नहीं उठता।

Low participation of Women in JRY in Maharashtra

*240. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in a recent study of Jawahar Rozgar Yojna (JRY) it has been found that the share of women in employment generation under JRY at the district and village levels was very meagre in Maharashtra;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what steps Government propose to initiate to increase the participation of women in JRY in Maharashtra and other parts of the country?

THE MINISTER OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI K. YERRAN NAIDU): (a) and (b) The Concurrent Evaluation of Jawahar Rozgar Yojana (JRY) (January-December, 1992) published in July, 1994 indicates the share of women in employment generation in Maharashtra is 31.99 per cent.

(c) As per the JRY guidelines 30% of the employment opportunities under JRY are reserved for women. This aspect is regularly monitored in all the States including Maharashtra through monthly, quarterly and annual progress reports. The implementation is also monitored through State Level Coordination Committee, various Vigilance Committees, the Area Officer reviews as well as various other mechanisms.

Indo-Oman Gas Project

1183. SHRI H. HANUMANTHAPPA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the progress of Indo-Oman Gas Project;

(b) whether it passes through Pakistani waters;

(c) whether there is any plan to take it to Mangalore to avoid Pakistani waters; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI T.R. BAALU): (a) The feasibility study taken up by the Oman Oil Company is yet to be completed.

(b) No, Sir.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Housing Schemes with Foreign Assistance

1184. **Shri Sanjay Dalmia:** Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the States where housing schemes with foreign assistance have been introduced; and

(b) the manner in which the foreign assistance is being utilised?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS & EMPLOYMENT (DR. U. VENKATESWARLU): (a) and (b) Kfw of Germany has provided/ committed loan/grant assistance of DM 170 million to HUDCO and DM 55 million to HDFC for financing low-cost housing schemes for economically weaker sections and slum improvement programmes in urban and rural areas of the country. The assistance is being utilised by these institutions to provide loans to housing agencies in various States for the implementation of specific housing projects approved by KfW. The States where such projects have so far been undertaken are as follows:

1. Andhra Pradesh
2. Gujarat
3. Jammu & Kashmir
4. Haryana
5. Karnataka
6. Kerala
7. Maharashtra
8. Punjab
9. Rajasthan
10. Tamil Nadu
11. Uttar Pradesh
12. West Bengal
13. Orissa

Housing projects of some other States are also expected to be covered in the new credit lines.

In addition, the World Bank has also extended credit for financing a reconstruction and relocation programme in the earthquake-affected areas of Latur and Osmanabad in Maharashtra.

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु धन

1185. **श्री अजीत जोगी:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रति वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु राज्य-वार कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) विकास परियोजनाओं के नाम क्या हैं और परियोजना-वार प्रत्येक राज्य को कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध न होने के कारण विकास कार्यों को अधूरा छोड़ दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या ठोस उपाय किये हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा): (क) और (ख) जवाहर रोजगार योजना (जे आर वाई), सुनिश्चित रोजगार योजना (ई ए एस), समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी), ग्रामीण जल सप्लाई, ग्रामीण स्वच्छता, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (डी पी ए पी) तथा मरूभूमि विकास कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए प्रमुख कार्यक्रम हैं। पिछले दो वर्षों के दौरान इन कार्यक्रमों के लिए आवंटित कुल निधियों को अनुपत्र में दर्शाया गया है। [देखिए परिशिष्ट 178, अनुपत्र संख्या 29]

(ग) और (घ) राज्य सरकारों से ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

Funds for Koel-Karo Hydro project

1186. SHRI GAYA SINGH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Koel-Karo Hydro Project is being delayed due to negligence of the Centre in releasing funds; and

(b) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (DR. S. VENUGOPALACHARI): (a) and (b) No, Sir. The 710 MW Koel Karo Hydro-electric Project in Bihar was entrusted to National Hydro-electric Power Corporation (NHPC) for execution in August 1980. Active start of the Project was not possible due to continued local resistance. The NHPC has also not been able to mobilise funds for the Project. NHPC will have to rely on market borrowings and/or external assistance to meet a substantial portion of the Project cost which is presently estimated around Rs. 2,400 crores. The Project was posed for assistance to OECF, Japan, but the response of the OECF has not been favourable.

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों हेतु राज्यों को सहायता

1187. **श्री रामजीलाल:** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को, विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों के उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा राज्यों को क्या सहायता उपलब्ध कराई जा रही है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में हरियाणा को कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई और किन-किन क्षेत्रों में इस उद्योग को बढ़ावा मिला है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नीतियों को उदारीकृत किया है और अल्कोहल पेयों के किण्वन और आसवन तथा लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों को छोड़कर सभी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को लाइसेंसमुक्त कर दिया है। सरकार ने विभिन्न वित्तीय राहतें भी उपलब्ध कराई हैं और घरेलू/अनिवासी भारतीय/विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए उपाय किए हैं इसके लाभ हरियाणा राज्य को भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा, मंत्रालय अनेक योजना स्कीमें भी चला रहा है जिसके तहत राज्य सरकार के संगठनों/सहायता प्राप्त/संयुक्त क्षेत्र की कंपनियों/स्वैच्छिक संगठनों/सहकारी संस्थाओं आदि को खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना/अपग्रेडिंग, किसानों के साथ बैकवर्ड लिंकेज के विकास, विपणन समर्थन, सुअर मांस, पॉल्ट्री और अन्य